



2026:AHC-LKO:39847-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

सिविल विविध पुनर्विचार आवेदन संख्या – 72 वर्ष 2026

मोहम्मद असलम

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत,
लखनऊ और 9 अन्य

.....विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : भगवती प्रसाद निगम, अनुराग शुक्ला

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या – 2

माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. सुना।
2. यह पुनर्विचार प्रार्थना-पत्र दिनांक 21 अप्रैल, 2026 के आदेश के विरुद्ध इस आधार पर दायर की गई है कि वैकल्पिक मार्ग पर एक अतिरिक्त बिजली का खंभा लगाने का निर्देश देने वाला उक्त आदेश, विद्युत विभाग की वितरण कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए एक अवैध

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तर्क के आधार पर प्राप्त किया गया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य निजी प्रतिवादी संख्या 8 से 10 को अनुचित लाभ पहुंचाना था।

3. पुनर्विचार याचिका की जांच करने पर, हमारा यह मत है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21 अप्रैल, 2026 को पारित आदेश में न तो कोई नए तथ्य या साक्ष्य मिले हैं और न ही अभिलेख में कोई स्पष्ट त्रुटि है। न्यायालय को उक्त आदेश की पुनर्विचार के लिए कोई अन्य पर्याप्त कारण भी नहीं मिलता है।

4. यह ध्यान देने योग्य है कि पुनर्विचार क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार है और यह कुछ सिद्धांतों द्वारा शासित होता है जिन्हें **कलकत्ता उच्च न्यायालय के पश्चिम बंगाल राज्य बनाम राज्य सरकारी कर्मचारी संघ (2019 एससीसी ऑनलाइन कलकत्ता 9181)** के फैसले में संक्षेप में बताया गया है। फैसले का प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे उद्धृत किया गया है:

"3.इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को पढ़ने और समझने पर निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:-

क. पुनर्विचार करने की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित है और उच्च न्यायालय रिट याचिका में पारित अपने स्वयं के आदेश/निर्णय की पुनर्विचार कर सकता है।

ख. पुनर्विचार की यह शक्ति सीमित शक्ति है और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 के साथ पढ़े गए धारा 151 के सिद्धांतों द्वारा शासित होगी।

ग. प्रथम, न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय की पुनर्विचार तब कर सकता है जब कोई नया और महत्वपूर्ण मामला या साक्ष्य सामने आए जो उचित सावधानी बरतने के बावजूद पुनर्विचार चाहने वाले पक्ष के ज्ञान में नहीं था या ठोस कारणों से प्रस्तुत नहीं किया जा सका। द्वितीय, न्यायालय अभिलेख में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली किसी गलती या त्रुटि के कारण अपने आदेश या निर्णय की पुनर्विचार कर सकता है। तृतीय, आदेश 47 के नियम 1 में 'अवशिष्ट खंड' किसी अन्य

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पर्याप्त कारण' के लिए पुनर्विचार का प्रावधान करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर यह माना है कि तीसरी शर्त "किसी अन्य पर्याप्त कारण" को पहली दो शर्तों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

घ. वह त्रुटि जो स्वतः स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क प्रक्रिया द्वारा पता लगाना पड़ता है, वह अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि नहीं है।

ङ. पुनर्विचार याचिका का उद्देश्य सीमित होता है और इसे "अपील का छिपा हुआ रूप" नहीं माना जा सकता। एक त्रुटिपूर्ण निर्णय जिसके विरुद्ध केवल अपील की जा सकती है और अभिलेख में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली त्रुटि जिसकी पुनर्विचार की जा सकती है, के बीच स्पष्ट अंतर है।

[देखें सासी (डी से एलआर बनाम अरविंदाक्षन नायर (2017) 4 एससीसी 692 में रिपोर्ट किया गया। हरिदास दास बनाम उषा रानी बनिक (2006) 4 एससीसी 78, पैरा 15-18 में रिपोर्ट किया गया; पारसियन देवी बनाम सुमित्री देवी (1997) 8 एससीसी 715, पैरा 7-10 में रिपोर्ट किया गया; अरिबाम तुलेश्वर शर्मा बनाम अरिबाम पिशक शर्मा ने (1979) 4 एससीसी 389, पैरा 3 में रिपोर्ट किया।]

4. निर्णयों की अंतिम वैधता को अधर में छोड़े जाने के संबंध में एक और पहलू को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिसका वर्णन न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने पी.एन. ईश्वर अय्यर बनाम रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (1980) 2 एससीआर 889; (1980) 4 एससीसी 680 में बहुत ही खूबसूरती से किया है, जिसमें वे खेद व्यक्त करते हुए कहते हैं:

"..... बिना जांच-पड़ताल के पुनर्विचार करना कभी भी नियम नहीं रहा है। इसके लिए उचित आधार होना आवश्यक है। अन्यथा, प्रत्येक निराश वादी नियमित पुनर्विचार के माध्यम से अपनी हार का बदला ले सकता है और इस प्रकार प्रारंभिक जांच या सावधानीपूर्वक अंतिम सुनवाई के लिए लंबी कतार में पड़े नए मामलों के निपटारे में बाधा डाल सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. न्यायमूर्ति अय्यर ने आगे इस प्रकार कहा है:

"तुच्छ पुनर्विचार याचिकाएं मुकदमेबाजी में जुए का तत्व भड़का देंगी, जिससे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की अंतिम वैधता अधर में लटक जाएगी। यदि प्रत्येक पराजित पक्ष 'पुनर्विचार' याचिका दायर करे और यदि संयोगवश कुछ मामलों में विरोधी पक्ष को नोटिस जारी कर दिया जाए, तो बाद वाला - और निश्चित रूप से, पहले वाला भी - भारी खर्च और चिंता में पड़ जाएगा। न्यायिक न्याय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंतिम निर्णय की गंभीरता ही नष्ट हो जाएगी यदि ऐसा खेल लोकप्रिय हो जाए।"

5. उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, पुनर्विचार याचिका अपील का छिपा हुआ रूप प्रतीत होती है, और तदनुसार, इसे **खारिज** किया जाता है।

जून 2, 2026

सीकेएस/-

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।